or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

There are no amendments to clauses 2 to 32. The question is :

"That clauses 2 to 32 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 32 were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are no amendments to the Schedule. The question is :

"That the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Schedule was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the, Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula, Preamble and the, Title were added to the Bill.

SHRI S.M. KRSHNA : I beg to move :

"That the Bill be passed".

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

" That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.01 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF THE TEXTILE UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) ORDINANCE, 1983.

Mr. DEPUTY SPEAKER : Now, we take up item Nos. 14 and 15 together. Shri Satnarayan Jatiya to move the statutory resolution.

SHRI SATYANARAYAN JATIYA (Ujjain) : Sir, I beg to move :

"This House disapproves of the Textile Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1983 (Ordinance No. 10 of 1983) promulgated by the President on the 18th October, 1983."

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने 13 कपड़ा उपक्रमों के प्रबन्ध को, उनके राष्ट्रीयकरण किये जाने तक, केन्द्रीय सरकार के हित में अधिकार का अध्यादेश जारी किया है, यह 18 अक्तूबर, 1983 को किया है जब कि वर्तमान सदन को चलने में 27 दिन बाकी थे। उन्होंने यह कहते हुए उपकार किया है कि 18 जनवरी, 1982 से जो हड़ताल चल रही थी या मिलबन्दी चल रही थी, उसके हल करने के लिये यह अध्यादेश जारी किया है।

20, 21 महीने तक मजदूर तड़पते रहे, मिलें चली नहीं, उनकी हालत खराब हो गई,

[श्री सत्यनारायण जटिया]

तब जाकर हमारी सरकार को खबर लगी कि इन मिलों को चलाना जरूरी हो गया है। अगर नहीं चलाया गया तो मजदूरों और मिलों की हालत खराब हो जायेगी। मजदूर 20-21 महीनों तक परेशान रहे, उनकी बात सुनी नहीं गई, वह भूखमरी के कगार पर आ गये उसके बाद सरकार ने यह उपकार किया है। सरकार की नीति इसी प्रकार से काम करने की है। वह काम तो करती है किन्तु उपकार जताकर करती है। मैं मान लेता हूँ कि मजदूरों के लिये, मिलों को चलाकर बहुत एहसान किया है, सरकार करती तो है किन्तु तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देर है अन्धेर नहीं है।

मैं वाणिज्यमंत्री से यह कहना चाहूँगा कि जिन 13 मिलों का अधिग्रहण किया गया है, उसके आधार भी दिये गये हैं जिसमें कहा गया है कि कुप्रबन्ध के कारण और असंतोष-जनक वित्तीय स्थिति के कारण उनका अधिग्रहण करना जरूरी हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब उनका सुप्रबन्ध होगा और उनकी वित्तीय स्थति को सुधारा जायेगा। कुप्रबन्ध का कारण है कि जितनी मिलें ली गई हैं, उसमें मशीनरी या कारखाने में लगने वाली चीजें ठीक नहीं हैं, सरकार उनको सुधारेगी। यह प्रश्न हमारे लिये जरूरी है, क्योंकि किसी भी संस्थान के संचालन के लिये रा-मैटीरियल, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और उसका प्रबन्ध किन लोगों के हाथों में है, यह बात देखने वाली है। अब तक के अनुभव के बारे में मैं आपको बताता हूं।

सरकार के पास एन० टी० सी० की 112 मिले हैं और उसके लाभ-हानि सब जानते हैं। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूंगा।

इन सारी 112 कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूर लगभग 2 लाख हैं। इस देश में कपड़ा उद्योग में 1 लाख मजदूर काम करते हैं। इन 12 लाख में से एन० टी० सी० की मिलों में 2 लाख मजदूर काम करते हैं।

1981-82 की प्रोडक्शन की हालत को देखिये। देश की कुल कपड़ा मिलों का उत्पादन 99, 650 लाख मीटर था। इन मिलों का उत्पादन जो हैंडलूम से और प्राइवेट मिलों के माध्यम से थे, उसका यदि विश्लेषण करें तो मिलों से जो कपड़ा उत्पादित हुआ है वह 3055 मीटर है, पावर लूम से 3797 मीटर है और हाथकरघा से 3113 मीटर है। इस प्रकार से एन० टी० सी० की मिलों ने 29 परसेंट उत्पादन किया है। जो मिलें उत्पादन कर रही हैं वह 803 हैं जिसमें स्पिनिंग मिलें 522 हैं और कम्पोजिट मिलें 281 हैं। आज सारे देश में मिलों के संचालन और उत्पादन की हालत ठीक नहीं है। कपड़ा उद्योग हमारे देश का बहुत पुराना उद्योग है। टेक्स्टाइल इंडस्ट्री एक लेबर-बेस्ड इंडस्ट्री है। उसमें मजदूरों के अधिक से अधिक काम करने की आवश्यकता होती है। इसलिए यह भी आवश्यक है कि उसमें से अधिक से अधिक मजदूरों को काम मिले लेकिन मिलों में स्वचलीकरण और आधुनिकीकरण लागू करते हुए इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि इससे मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। वैसे भी हमारा देश बेरोजगारी से पीड़ित है। आदमी को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं वह कोई आजीविका का साधन पाता है।

कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूर को चाहे जितना भी पैसा मिले, लेकिन समाज में उसको सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता। उसको मवाली के नाम से पुकारा जाता है। जेल में रहने वाले कैदियों को बैरक की तरह उन लोगों के रहने के लिए मिलों की चाल होती है, जहां उनके परिवार के रहने के लिए पर्याप्त जगह तथा सुविधाएं नहीं होतीं। यह वास्तविकता है कि हमारे देश में न तो कपड़ा मिलों की हालत ठीक है और न उनमें काम करने वाले मजदूरों की हालत ठीक है। कपड़ा मिलें न केवल देश के उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन करती हैं, बल्कि विदेशों में कपड़ा भेज कर फ़ारेन एक्सचेंज भी अर्जित करती हैं। जहां तक इन मिलों के उत्पादन का सम्बन्ध है, आजादी के बाद स्थिति यह है कि लोगों के पहनने के लिए कपड़ा मुहैया नहीं है।

बम्बई की कुछ मिलें ठीक काम कर रही हैं। उनकी व्यवस्था इस पर निर्भर करती है कि वे किस प्रकार माल को खरीदती हैं, किस प्रकार उसको प्रोसेस करती हैं और किस प्रकार अपने उत्पादन को मार्केट में लाती हैं। एन० टी० सी० द्वारा बीमार मिलों का अधिग्रहण किया जाता है, लेकिन वे बीमारी में से उबर नहीं पातीं। बीमारी से उबारने के लिए उचित उपचार के अभाव के कारण वे स्वस्थ नहीं हो पातीं।

इस सम्बन्ध में इन्दौर के होप टेक्स्टाइल की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह एक प्राईवेट कनसर्न है। पहले वह मिल अच्छी तरह चलती थी। लेकिन मिल-मालिक ने घाटा बता कर उसको बन्द कर दिया। वहां पर चार हजार से ज्यादा जो मजदूर काम करते थे, आज वे बेकार और बेरोजगार हैं और उनके पास गुजारे के लिए कोई साधन नहीं है। इसलिए वहां पर श्रमिक असंतोष है। इन्दौर की सब मिलों के मजदूरों ने उसके समर्थन में एक दिन की हड़ताल की।

मैं हड़ताल का पक्षधर नहीं हूं, किन्तु हड़ताल मजदूर का आखिरी कदम है। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि वह अपने रोजगार और अपनी मजदूरी की कीमत पर हड़ताल करे, क्योंकि जब तक वह मजदूरी कमायेगा नहीं, तब तक वह अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेगा। मजदूर हड़ताल तब करता है, जब वह बहुत परेशान हो जाता है और उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। श्रम मंत्रालय के पास जो कानून हैं, वे बहुत पंगु हैं—वे इतने सक्षम नहीं हैं कि मजदूरों के बारे में ठीक समय पर ठीक फैसला किया जा सके। आज श्रम कानूनों और औद्योगिक विवाद सम्बन्धी काननों के अधूरे होने के कारण भी सारे देश में यह स्थिति निर्मित हुई है।

सरकार ने ये 13 मिलें ले ली हैं, लेकिन अभी और भी बहुत सी मिलें प्रतीक्षा कर रही हैं कि सरकार उनके बारे में क्या निर्णय लेती है ? जैसे, अहमदाबाद में कुछ मिलें हैं, इंदौर की होप टेक्स्टाइल है, उज्जैन की विनोद तथा विमल मिलें हैं, पांडीचेरी की एंग्लो-फ्रेंच मिल है। आज सारे देश में टेक्स्टाइल उद्योग नष्ट हो रहा है। ऐसा लगता है कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा है, कपड़ा उद्योग हमारे देश का सबसे पुराना उद्योग है। पहले गांवों में जुलाहे काम करते थे। उसके बाद शहरों में कपड़ा मिलें स्थापित हुईं। समय-समय पर उनका आधुनिकीकरण-माडर्नाइजेशन और स्वचालीकरण—आटोमेटाइजेशन—होता रहा है।

[श्री सत्यनारायण जटिया]

इन सबके बावजूद आज भी कपड़ा उद्योग में मुनाफ़ा नहीं है और न ही उसमें काम करने वाले मजदूरों की हालत अच्छी है। एक्सपोर्ट के आंकड़े देखने से पता लगता है कि टेक्स्टाइल उद्योग द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा में भी काफ़ी गिरावट आई है।

मेरा निवेदन यह है कि हम टेक्स्टाइल उद्योग पर अलग से विचार न करें। उद्योग पूंजी और पसीने का मिला-जुला उपक्रम है। अगर हम सोच लें कि पूंजी लगा कर हमारा काम बन जाएगा, तो यह नहीं हो सकता। हमारी नीयत यह होनी चाहिए कि किसी भी उद्योग में पूंजी और पसीने को बराबर का हक और हिस्सा होना चाहिये।

14.00 hrs.

किन्तु होता यह है कि पूंजी का तो आप सम्मान करते हैं क्योंकि पूंजी के बिना तो कोई काम चलता नहीं, परन्तु जो पसीना बहाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो श्रम के आधार पर उत्पादन करते हैं उनकी सतत उपेक्षा होती है। यह बात हमेशा के लिए चलने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कि राष्ट्र का उद्योगीकरण हो, उसके अन्दर ऐसे उद्योग लगाए जाने चाहिए जिससे उद्योगों का श्रमिकीकरण हो। अधिक से अधिक श्रमिकों को उसमें काम मिले।

MR. DEPUTY SPEAKER : Are you going to conclude ?

SHRI SATYANARAYAN JATIYA : I want to continue.

MR. DEPUTY SPEKFR : All right. You continue next time.

14.01 hrs

DISCUSSION ON PRESENT INTERNATIONAL SITUATION AND THE POLICY OF THE GOVERNMENT OF INDIA IN RELATION THERETO.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now we take up the international situation.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P.V. NARASIMHA RAO) : I beg to move :

> "That this House do consider the present international situation and the policy of the Government of India in relation thereto."

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved :

> "That this House do consider the present international situation and the policy of the Government of India in relation thereto.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : I beg to move :

> 'That for the original motion, the following be substituted namely :—
>
> This House, having considered the present international situation and the policy of the Government of India in relation thereto, recommends in the national interest that the Government change the present policy of confrontation with the neighbours to that of promoting amity, and also maintain equidistance from the big powers USA and USSR'"

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved :

> "That for the original motion, the following be substituted namely :—
>
> This House, having considered the present international situa-